भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *322

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

पंचायती राज प्रणाली में पारदर्शिता

*322. श्री सुनील कुमार पिंटू:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रत्येक पंचायत और स्थानीय निकायों को अपनी वेबसाइटों बनाने तथा संबंधित पंचायत एवं स्थानीय निकाय से संबंधित प्रत्येक कार्यकलाप को अपलोड करने की अनुमति देकर पंचायती राज प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

पंचायती राज प्रणाली में पारदर्शिता के संबंध में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं 322 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) 'पंचायत' राज्य का विषय है। पंचायतों में प्रशासन प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश (संघ शासित प्रदेशों) शासन का दायित्व है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की पहल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती हैं। पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें आयोजना, बजटन, कार्यान्वयन, लेखांकन, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, कर संग्रह आदि सेवाएं प्रदान करने सहित पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स का एक सूइट विकसित किया गया है। ये एप्लीकेशन्स सामूहिक रूप से पंचायत एंटरप्राइज सूइट (पीईएस) के हिस्से हैं। पीईएस के तहत आने वाले राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (एनपीपी) एक एप्लीकेशन है, जो पंचायतों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) की वेबसाइट के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इन विशिष्ट वेबसाइटों को https://www.panchayatportals.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है , जिसमें 1,52,747 पंचायतों/ ग्रामीण स्थानीय निकायों की वेबसाइटें पहले ही सक्षम हो चुकी हैं और इनमें से 1,23,093 पंजीकृत भी हो चुकी हैं। चूंकि 'पंचायत' राज्य का विषय है, पंचायती राज मंत्रालय ने न केवल राज्यों को वेबसाइट विकास हेतु एक साधन/टूल प्रदान किया है, अपितु वेबसाइट विकास एवं पंचायतों के आंकड़ों के डिजीटलीकरण हेतु उनका अनुशीलन भी करता है।

*****